



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 718] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 15, 1990/अग्रहायण 24, 1912
No. 718] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 15, 1990/AGRAHAYANA 24, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

पर्यावरण और वन मंत्रालय

(पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1990

उद्योगों की स्थापना, संक्रियाओं या संसाधनों आदि पर निम्नलिखित निबंधन
अधिशेषित किए जाएंगे, अर्थात्:—

2. प्रविष्टि क्रियाकलाप।

निम्नलिखित क्रियाकलाप तटीय विनियमन परिक्षेत्र के भीतर प्रतिष्ठित
किए जाते हैं, अर्थात्:—

का.आ. 944(अ):—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण)
प्रविनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के
खंड (5) के माध्यम से उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग
करते हुए, तटीय क्षेत्रों का संरक्षण करने के लिए और यह सुनिश्चित करने
के लिए कि तटीय क्षेत्रों में प्रयोग और क्रियाकलाप पर्यावरणीय संरक्षण
के सिद्धांतों और अपेक्षाओं से संगत हैं, आवश्यकता पर विचार करने के
पश्चात् प्रस्थापना करती है कि समुद्रों, खादियों, मांगर संग्रहों और संकरी
खादियों के ऐसे तटीय आयामों को जो ऊर्ध्व ज्वार रेखा से 500 मीटर
तक स्थल की ओर ज्वारी क्रिया से प्रभावित हैं तथा निम्न ज्वार रेखा
और ऊर्ध्व ज्वार रेखा के बीच की भूमि को तटीय विनियमन परिक्षेत्र के
रूप में घोषित किया जाए और उक्त तटीय विनियमन परिक्षेत्र में

- ऐसे उद्योगों को छोड़कर, जो नीचे तटीय तट भाग से
संबंधित हैं या जिन्हें तटाय सुविधाओं की आवश्यकता है
उद्योगों की स्थापना;
- भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचनाओं
सं. का.आ. 594(अ), तारीख 28 जुलाई, 1989 का.आ.
966 (अ), तारीख 27 नवम्बर, 1989 और का.नि.प्र.
1037(अ), तारीख 5 दिसम्बर, 1989 की अधिसूचनाओं
में विनिर्दिष्ट रूप से परिसंकटमय पदार्थों का विनिर्माण या
हस्तांतरण या संग्रहण या व्यय;
- मत्स्य संसाधन इकाइयाँ जिनके अन्तर्गत भांडारकरण भी हैं।
- अपशिष्टों और बहिःस्त्रावों के व्ययन के लिए इकाइयों यांत्रिकों
की स्थापना;

3327GI/90

(1)

- (v) उद्योगों, नगरों या शहरों और अन्य मानव व्यवस्थापनों से प्रस्तावित अपशिष्ट और बहिष्कारों का निस्सारण;
- (vi) भूमि भरने के प्रयोजन के लिए या अन्यथा तदन निगम अपशिष्ट का ढप करना;
- (vii) तापीय विद्युत केन्द्रों से, राख का ढप करना;
- (viii) समुद्र जल के प्राकृतिक क्रम की समरूप बाधाओं के साथ धार करना या उसमें बाधा डालना सिवाए, उसके जो तटीय कटाव के नियंत्रण के लिए अपेक्षित है;
- (ix) भूमि पुनर्स्थापन, बालू, बहानों और अन्य अवस्तर सामग्री की खनीयता;
- (x) भस्म संग्रहण या भूजल का निकासन तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए उसका सन्निर्माण या यांत्रिकी;
- (xi) उपाबंध में विनिर्दिष्ट रूप में पारिस्थितिक रूप से सुग्राही क्षेत्रों में सन्निर्माण क्रियाकलाप;
- (xii) निर्दिष्ट ज्वार रेखा और उच्च ज्वार रेखा के बीच कोई सन्निर्माण क्रियाकलाप; और
- (xiii) बालू टिब्बा, पहाड़ों, प्राकृतिक विशेषताओं की सजावट अथवा उसमें परिवर्तन करना जिसके अन्तर्गत सुन्दर बनाने मनोरंजन संबंधी और अन्य प्रयोजनों के लिए भूस्थ परिवर्तन भी हैं।

3. अनुज्ञेय क्रियाकलापों का विनियमन।

अन्य सभी क्रियाकलाप, उनके सिवाय जो ऊपर पैरा 2 में प्रतिषिद्ध है निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे:—

- (1) तटीय विनियमन परिक्षेत्र के भीतर किसी क्रियाकलाप के लिए अनुज्ञा केवल तभी दी जाएगी जब निरन्तर रूप से यह साबित हो जाए कि ऐसा क्रियाकलाप परिक्षेत्र की सीमा के बाहर नहीं किया जा सकता है।
- (2) निम्नलिखित क्रियाकलापों के लिए भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुज्ञा अपेक्षित होगी; अर्थात्:—
 - (i) सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं से संबंधित सन्निर्माण क्रियाकलाप जिनके लिए तट समाप्त सुविधाएं आवश्यक हैं (उदाहरणार्थ जलाशय निर्माण, मंच, जैदी आदि);
 - (ii) ऐसे पत्तों और बन्दरगाहों तथा प्रकाश स्तम्भों के लिए सन्निर्माण के अन्तिम चरण जिनके लिए नग्न अध्रमण अपेक्षित हैं;
 - (iii) तापीय विद्युत संयंत्र; और
 - (iv) पांच करोड़ रुपए से अधिक निविदाएं वाले अन्य सभी क्रियाकलाप।

(3) (i) तटीय राज्य और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अपने-अपने राज्यक्षेत्रों के भीतर उपाबंध 1 में दिए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार तटीय प्रायामों का पता लगाकर और उनका वर्गीकरण करके तटीय परिक्षेत्र प्रबंध योजना तैयार करेंगे और केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय का अनुमोदन अधिप्राप्त करेंगे तथा भूमि उपयोग आदि पर सुसंगत कानूनों और विनियमों में इन्हें सम्मिलित करेंगे।

(ii) ऐसी अनुमोदित योजनाओं की रूपरेखा के भीतर जो क्रियाकलाप ऊपर पैरा 2 और पैरा 3(2) में सम्मिलित नहीं है किए गए हैं, वे उपाबंध 1 में दिए गए मार्गदर्शकों के अनुसार यथास्थिति, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा विनियमित किए जाएंगे।

4. मानीटर करने और प्रवर्तन के लिए प्रक्रिया:—

पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र और राज्य या संघ राज्यक्षेत्र स्तरों पर ऐसे अन्य प्राधिकरण, जो इस

प्रयोजन के लिए अधिष्ठाता किए जाएं, इस अधिसूचना के संशोधित उद्देश्य को मानीटर करने और उनके प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी होंगे।

5. आक्षेप संग्रह:

पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (ख) के अधीन यह अधिसूचित किया जाता है कि ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रस्तावित निदेश के विरुद्ध कोई आक्षेप फाइल करने का इच्छुक है इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन के भीतर भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय पर्यावरण, वन और अन्य जीव विभाग, नई दिल्ली के सचिव की लिखित में ऐसा कर सकेगा।

[ए.के. 15019/1/84-आई.ए.-III (फिन्स)]

महेश प्रसाद, सचिव

अनुबन्ध-1

तटीय क्षेत्र वर्गीकरण और विकास नियमन

तटवर्ती नियमन क्षेत्र का वर्गीकरण

6(1) विकास गतिविधियों के विनियमन के लिए भूमि की और उच्च ज्वार रेखा के 500 मीटर के भीतर के तटवर्ती भागों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात्:—

श्रेणी-1 (सी.आर.जेड-1):—

राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, प्रारक्षित वनों, कच्छ वनस्पति, सूंग मछली और अन्य समुद्री जीवों के प्रजनन क्षेत्र और झंडे देने वाली भूमि प्राकृतिक सुन्दरता वाले पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्र तथा केन्द्र सरकार या राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश स्तर पर संबंधित प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर अधिसूचित इस प्रकार के अन्य क्षेत्र।

श्रेणी-2 (सी.आर.जेड.-2):—

समुद्री किनारों या उनके नजदीक तक पहले ही से विकसित क्षेत्र इस प्रयोजन के लिए "विकसित क्षेत्र" का आशय नगरीय सीमाओं के अन्दर उस क्षेत्र से है जहाँ पहले ही काफी निर्माण हो चुका है और जहाँ जल निकासी और पठुंध मार्ग तथा जल आपूर्ति और मुख्य संचालन विकास जैसी अन्य आधारभूत सुविधाएं सुहृदय कराई गई हैं।

श्रेणी-3 (सी.आर.जेड.-3):—

वे क्षेत्र जो अपेक्षाकृत शांत क्षेत्र हैं और जो श्रेणी-1 व 2 के अन्तर्गत नहीं आते हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में तटीय क्षेत्र (विकसित और अविकसित) और नगरीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्र आयेंगे, जहाँ पर्याप्त विकास नहीं हुआ है।

श्रेणी-4 (सी.आर.जेड.-4):

सी.आर.जेड-1, सी.आर.जेड-2 और सी.आर.जेड-3 में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को छोड़कर अंशमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह के तटीय भाग।

गतिविधियों के नियमन के लिए मापदंड:

6(2) तटीय भागों की विशिष्ट श्रेणियों में विकास या निर्माण गतिविधियों को निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र स्तर पर संबंधित प्राधिकारियों द्वारा नियंत्रित किया जायेगा।

सी.आर.जेड-1

उच्च ज्वार रेखा के 500 मीटर के अन्य किसी नए निर्माण की अनुमति नहीं है।

आर. जेड-2

- (1) जहाँ समुद्र के किनारे और विकसित किये जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्र को अलग करने वाला कोई मार्ग है उस स्थिति में विद्यमान मार्ग के भूमि की ओर ही नए निर्माण की अनुमति दी जाए, बशर्ते कि एक एस आई/एफ ए आर के लिए विद्यमान मापदंडों सहित स्थानीय टाउन और कंट्री प्लानिंग विनियमों का पालन किया जाए।
- (2) जहाँ किनारे के क्षेत्रों तथा आसपास के विकास को अलग करने वाला कोई मार्ग नहीं है, उस स्थिति में मीजूदा, संरचनाओं के समुद्र की ओर स्थानीय टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विनियमों के अर्थात् भवनों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (3) विद्यमान एक एस आई/एफ ए आर मापदंडों का अनुपालन करने और विद्यमान प्रयोग में परिवर्तन किए बिना प्राधिकृत भवनों के पुनः निर्माण की अनुमति दी जायेगी।
- (4) भवनों की अभिकल्प और निर्माण स्थानीय वास्तुकला और प्राकृतिक दृश्यों के अनुरूप होना चाहिए।

सी. आर. जेड-3

- (1) उच्च उबार रेखा से 200 मीटर तक के क्षेत्र को "विकास क्षेत्र नहीं" माना जाता है और इस क्षेत्र के अन्दर किसी भी तरह के निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (2) अनुबन्ध-2 में उल्लिखित विनियमों में निर्धारित शर्तों के अर्थात् किराए के लिए आवास होटल/समुद्री किनारों पर सैरगाह हार्नेडे हांम्स के निर्माण के लिए उच्च उबार रेखा के 200 मीटर और 500 मीटर के बीच के खाली प्लोटों के विकास की अनुमति है।
- (3) उच्च उबार रेखा के 200 मीटर और 500 मीटर के बीच आवास इकाइयों के निर्माण/पुनः निर्माण की अनुमति है बशर्ते कि यह परम्परागत अधिकारों और प्रयोगों की परिधि में आना हो। इस प्रकार के निर्माण/पुनः निर्माण की अनुमति अनुबन्ध-2 में दिए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार दी जायेगी।
- (4) उपरोक्त (1) से (3) की शर्तों पर विद्यमान प्राधिकृत भवन के पुनः निर्माण/उसमें परिवर्तन करने की अनुमति है।

सी. आर. जेड-4

अवमान और निकटवर्ती द्वीप समूह:

- (1) उच्च उबार रेखा के 200 मीटर के भीतर भवन निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (2) उच्च उबार सीमा से 200 तथा 500 मीटर के बीच स्थित भवन 2 तल (निचला तल और प्रथम तल) से अधिक ऊंचाई के नहीं होने चाहिए, कुल आच्छादित क्षेत्र भूमि के टुकड़े का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए तथा निर्माण की कुल ऊंचाई 9 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (3) भवनों का निर्माण और डिजाइन स्थानीय वास्तुकला तथा उस स्थान के परिवेश से मेल खाना चाहिए।
- (4) तटों और तटीय जल की मृगा चट्टानों तथा बालू को निर्माण कार्यों के उपयोग में नहीं लाना चाहिए।
- (5) मृगा चट्टानों में तथा उनके आसपास तलमार्जन तथा जल के भीतर विस्फोट करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए तथा
- (6) तथापि, कुछ द्वीपसमूहों में तटीय भागों को भी सी. आर. जेड-1 अथवा 2 अथवा 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है और इस प्रकार के नामित भागों में संबंधित श्रेणियों के लिए उपयुक्त विनियम लागू होंगे।

लक्षद्वीप समूह

- (1) भवन निर्माण की अनुमति देते समय द्वीप समूहों के आकार के अनुसार उच्च उबार सीमा की दूरी निर्दिष्ट करनी चाहिए। इसका निर्धारण विशेषज्ञों के परामर्श से जल-विज्ञानीय पहलुओं, भूमि कटाव तथा पारिस्थितिकीय संवेदनशीलता सहित स्थानीय परिस्थितियों की तुलना में विशिष्ट प्रयोजनों के लिए भूमि उपयोग का आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक द्वीप के लिए किया जाना चाहिए।
- (2) उच्च उबार रेखा के 500 मीटर के भीतर के भवन 2 तल (निचला तल तथा प्रथम तल) से अधिक ऊंचाई के नहीं होने चाहिए। कुल आच्छादित क्षेत्र भूमि के टुकड़े का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए तथा निर्माण की कुल ऊंचाई 9 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (3) भवनों का निर्माण और डिजाइन स्थानीय वास्तुकला तथा परिवेश से मेल खाना चाहिए।
- (4) तटों तथा तटीय जल की मृगा चट्टानों तथा बालू को निर्माण कार्यों के उपयोग में नहीं लाना चाहिए।
- (5) लैगून तथा मृगा चट्टानों में तथा उनके आसपास तलमार्जन जल के भीतर विस्फोट करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए तथा
- (6) तथापि, कुछ द्वीपसमूहों में तटीय भागों को भी सी. आर. जेड-1 अथवा 2 अथवा 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है और इस प्रकार के नामित भागों में संबंधित श्रेणियों के लिए उपयुक्त विनियम लागू होंगे।

अनुबन्ध-2

तटीय भागों में समुद्र-तट सैरगाह/होटल/आवास-गृह के लिए मार्ग-निर्देश

7. (1) तटीय भागों में समुद्र-तट सैरगाह/होटल/आवास-गृह के निर्माण के लिए निम्नलिखित शर्तें होंगी।

- (1) परियोजना प्रस्तावक उच्च उबार रेखा से 200 मीटर तक (भूमि की ओर) तथा निम्न उबार और उच्च उबार सीमा के बीच के क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य (अस्थायी निर्माण और कंटीली तार अथवा इस प्रकार के अन्य अवरोधों सहित) नहीं करेंगे।
- (2) आच्छादित क्षेत्र प्लॉट के आकार के 33 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। खुले क्षेत्र में उपयुक्त हरियाली से सही तरह से सु-दृश्य निर्माण किया जाना चाहिए।
- (3) निर्माण आस-पास के भू-दृश्य तथा स्थानीय वास्तुकला के अनुरूप होना चाहिए।
- (4) भवन की कुल ऊंचाई 9 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए और भवन दो मंजिलों (भूमि तल और प्रथम तल) से अधिक ऊंचा नहीं होना चाहिए।
- (5) केंद्रीय/राज्य भूमि जल बोर्ड की सहमति के बिना भूमि जल एच.टी.एल. से 500 मीटर के अन्दर से नहीं लिया जाना चाहिए।
- (6) उच्च उबार रेखा के 500 मीटर के भीतर भवन, तरणताल, तथा बेसमेंट, के बुनियादी ढांचे के अलावा रेत निकालने मशीनें भागों को समसज्ज बनाने या खुदाई करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(7) परियोजना क्षेत्र से शोधित बहिर्वाहों को अपशिष्टों उत्सर्जन की क्षमता और और स्तर आदि सक्षम प्राधिकरणों, जिसमें केन्द्रीय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शामिल है तथा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए।

(8) बहिर्वाहों और ठोस अपशिष्टों के शोधन के लिए आवश्यक प्रबन्ध किए जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि साफ न किए गए बहिर्वाहों और ठोस अपशिष्टों को जल या समुद्री किनारों पर न बहाया जाए।

(9) लोभ समुद्री किनारों तक आ सकें, इसके लिए किन्हीं दो प्लांटों के बीच कम से कम 20 मीटर चौड़ी पट्टी सुरक्षा कराई जाए; और,

(10) यदि परियोजना में घनतर प्रयोजनों के लिए वन भूमि की उपयोग में लाया जाना हो तो इसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मंजूरी लेने की आवश्यकता है। परियोजना के संबंध में लागू अन्य केन्द्रीय और राज्य कानूनों का अनुपालन किया जाना चाहिए।

7(2) पर्यावरणिकीय संवेदनशील क्षेत्रों में (जैसे मेरीन पार्क, कच्छ वनस्पति, मृगे चट्टानें, मछलियों के प्रजनन और अंडे देने की जगह तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य क्षेत्र) समुद्री सैरगाहों/होटलों/आवासों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

महेश प्रसाद, सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS (Department of Environment, Forests and Wildlife) NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 1990

S.O. 944 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) of sub-section (2), of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government, after considering the need for protecting the coastal areas and for ensuring that the use and activities in the coastal areas are consistent with the principles and requirements of environmental conservation, hereby proposes to declare that the coastal stretches of seas, bays, estuaries and creeks which are influenced by tidal action (in the landward side) upto 500 metres from the High Tide Line and the land between the Low Tide Line and the High Tide Line as Coastal Regulation Zone and to impose the following restrictions on the setting up of industries, operations or processes etc. in the said Coastal Regulation Zone, namely:—

2. Prohibited Activities

The following activities are declared as prohibited within the Coastal Regulation Zone, namely:—

- (i) setting up of industries except those directly related to sea front or directly needing shore facilities;
- (ii) manufacture or handling or storage or disposal of hazardous substances as specified in the Notifications of the Govt. of India in the Ministry of Environment and Forests

No. S.O. 594 (E) dated 28th July, 1989
S.O. 966 (E) dated 27th November, 1989
and GSR 1037 (E) dated 5th December, 1989;

- (iii) fish processing units including warehousing;
- (iv) setting of units/mechanisms for disposal of wastes and effluents;
- (v) discharge of untreated wastes and effluents from industries, cities or towns and other human settlements;
- (vi) dumping of municipal waste for the purposes of landfilling or otherwise;
- (vii) dumping of ash from thermal power stations;
- (viii) bunding or disturbing the natural course of sea water with similar obstructions, except those required for control of coastal erosion;
- (ix) land reclamation, mining of sands, rocks and other substrate materials;
- (x) harvesting or drawal of ground water and constructions or mechanisms thereof for such purposes;
- (xi) construction activities in ecologically sensitive areas as specified in Annexure;
- (xii) any construction activity between the Low Tide Line and High Tide Line; and
- (xiii) dressing or altering of sand dunes, hills, natural features including landscape changes for beautification, recreational and other such purposes;

3. Regulation of Permissible Activities.

All other activities, except those prohibited in para 2 above, will be regulated as under:

(1) Clearance shall be given for any activity within the Coastal Regulation Zone only if it is proved conclusively that such activity cannot be located beyond the zone.

(2) The following activities will require clearance from the Ministry of Environment and Forests, Government of India, namely:

- (i) Construction activities related to Defence requirements for which foreshore facilities are essential (e.g. slipways, jetties etc);
- (ii) operational constructions for ports and harbours and light houses requiring water frontage;
- (iii) thermal power plants; and
- (iv) all other activities with investment exceeding rupees five crores.

(3) (i) The coastal States and Union Territory Administration shall prepare Coastal Zone Manage-

ment Plans identifying and classifying the coastal stretches within their respective territories in accordance with the guidelines given in Annexure-I and obtain approval of the Central Govt. in the Ministry of Environment and Forests and incorporate these in the relevant statutes and regulations on land use etc.

(ii) Within the frame work of such approved plans, the activities not covered in para 2 and para 3 (2) above shall be regulated by the State Government, Union Territory Administration or the local authority as the case may be, in accordance with the norms given in annexure-I.

4. Procedure for monitoring and enforcement

The Ministry of Environment and Forests and the Government of State or Union Territory and such other authorities at the State or Union Territory levels, as may be designated for this purpose, shall be responsible for monitoring and enforcement of the amended provisions of this notification.

5. Inviting objections

It is notified under clause (b) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, that any person interested in filing any objection against the proposed direction, may do so in writing to the Secretary in the Department of Environment, Forests and Wildlife, Ministry of Environment and Forests, Government of India, New Delhi, within sixty days from the date of publication of this notification in the official gazette.

[No. K-15019/1/84-IA-III (Vol.II)]
MAHESH PRASAD, Secy.

ANNEXURE I

COASTAL AREA CLASSIFICATION AND DEVELOPMENT REGULATIONS

Classification of Coastal Regulation Zone:

6(1) For regulating development activities, the coastal stretches within 500 metres of High Tide Line on the landward side are classified into four categories, namely:—

Category I (CRZ-I) :

Areas that are ecologically sensitive and important, such as national parks, sanctuaries, reserve forests, mangroves, corals, areas close to breeding and spawning grounds of fish and other marine life, areas of outstanding natural beauty and such other areas as are notified by the Central Government or the concerned authorities at the State/UT level from time to time.

Category II (CRZ-II) :

The areas that have already been developed upto or close to the shore-line. For this purpose, "developed area" is referred to as that area within the municipal limits which is already substantially built up and which has been provided with drainage and approach road and other infrastructural facilities, such as water supply and sewerage mains.

Category III (CRZ-III) :

Areas that are relatively undisturbed and those which do not belong to Category-I & II. These will include coastal zone in the rural areas (developed and undeveloped) and areas within municipal limits where substantial development has not taken place.

Category IV (CRZ-IV) :

Coastal stretches in the Andaman & Nicobar and Lakshadweep island except those designated as CRZ-I, CRZ-II and CRZ-III.

Norms for Regulation of Activities :

6(2) The development or construction activities in different categories of coastal stretches shall be regulated by the concerned authorities at the State/Union Territory level, in accordance with the following norms :

CRZ-I

No new construction permitted within 500 metres of the High Tide Line.

CRZ-II

- (i) Where there is a road separating the beach and the area proposed to be developed, new constructions be permitted only on the landward side of the existing road, subject to the local Town & Country Planning Regulations, including the existing norms for FSI/FAR.
- (ii) Where there is no road separating the beach area and the surrounding development, construction of building shall not be allowed on the sea-ward side of the existing structures subject to the local Town and Country Planning regulations.
- (iii) Reconstruction of the authorised buildings to be permitted subject to compliance with the existing FSI/FAR norms and without change in the existing use.
- (iv) The design and construction of buildings should merge with the local architecture and landscape.

CRZ-III

- (i) The area upto 200 metres from the High Tide Line is to be earmarked as 'No development zone' and no construction shall be permitted within this zone.
- (ii) Development of vacant plots between 200 and 500 metres of High Tide Line permitted for construction of lodging houses/hotel/beach resorts/holiday homes subject to the conditions as stipulated in the guidelines at Annexure-II.
- (iii) Construction/reconstruction of dwelling units between 200 and 500 metres of the High

Tide Line permitted so long it is within the ambit of traditional rights and customary uses. Building permission for such construction/reconstruction will be in accordance with the guidelines at Annexure II.

- (iv) Reconstruction/alterations of an existing authorised building permitted subject to (i) to (iii) above.

CRZ-IV

Andaman & Nicobar Islands;

- (i) No construction of buildings shall be permitted within the 200 metres of the HTL;
- (ii) The buildings between 200 and 500 metres from the High Tide Line should not have more than 2 floors (ground floor and 1st floor), the total covered area should not be more than 50 per cent of the plot size and the total height of construction should not exceed 9 metres;
- (iii) The design and construction of buildings should merge with the local architecture and landscape;
- (iv) Corals and sand from the beaches and coastal waters should not be used for construction purposes;
- (v) Dredging and underwater blasting in and around coral formations should not be permitted; and
- (vi) However, in some of the islands, coastal stretches may also be classified into categories CRZ-I or II or III, and in such designated stretches, the appropriate regulations given for respective Categories would apply.

Lakshadweep Islands

- (i) For permitting construction of buildings, the distance from the High Tide Line should be decided depending on the size of the islands. This should be laid down for each island in consultation with the experts keeping in view the land use requirements for specific purposes vis-a-vis local conditions including hydrological aspects, erosion and ecological sensitivity;
- (ii) The buildings within 500 metres from the HTL should not have more than 2 floors (ground floor and 1st floor), the total covered area should not be more than 50 per cent of the plot size and the total height of construction should not exceed 9 metres;
- (iii) The design and construction of buildings should merge with the local architecture and landscape;
- (iv) Corals and sand from the beaches and coastal waters, should not be used for construction purposes.

- (v) Dredging and under water blasting in and around lagoons as coral formations should not be permitted; and,

- (vi) However, in some of the Islands, coastal stretches may also be classified into categories CRZ-I or II or III. In such designated stretches, the appropriate regulations given for respective categories would apply.

ANNEXURE II

Guidelines for beach resorts/hotels/lodging houses in the coastal stretches.

7(1) Construction of beach resorts/hotels/lodging houses in the coastal stretches will be subject to the following conditions:—

- (i) The project proponents will not undertake any construction (including temporary constructions and fencing or such other barriers) within 200 metres (in the landward side) from the High Tide Line and within the area between the low tide and high tide line;
- (ii) The covered area should not exceed 33 per cent of the plot size. The open area should be suitably landscaped with appropriate vegetal cover;
- (iii) The construction should be consistent with the surrounding landscape and local architectural style.
- (iv) The overall height of construction should not exceed 9 metres and the construction should not be more than 2 floors (ground floor plus one upper floor);
- (v) Ground water should not be tapped within 500 metres of the HTL without the concurrence of the Central/State Ground water Board;
- (vi) Extraction of sand, levelling or digging of sandy stretches except for structural foundation of building, swimming pool and basement, should not be permitted within 500 metres of the High Tide Line;
- (vii) The quality of treated effluents, solid wastes, emissions and noise level etc. from the project area must conform to the standards laid down by the competent authorities including the Central/State Pollution Control Board and under the Environment (Protection) Act, 1986;
- (viii) Necessary arrangements for the treatment of the effluents and solid wastes must be made. It must be ensured that the untreated effluents and solid wastes are not discharged into the water or on the beach;

- (ix) To allow public access to the beach, atleast a gap of 20 metres width should be provided between any two plots; and
- (x) If the project involves diversion of forests for non-forest purpose, clearance as required under the Forest (Conservation) Act, 1980 should be obtained. The requirements of other Central and State laws as applicable to the project should also

be met with.

7.(2) In ecologically sensitive areas (such as marine parks, mangroves, coral reefs, breeding and spawning grounds of fish, wildlife habitats and such other areas as notified by the Central/State Government), construction of beach resorts/hotels/lodging houses shall not be permitted.

MAHESH PRASAD, Secy.

14-12-90

